



www.tejyug.com

• मंगलवार, 05 मार्च, 2024
• Tuesday, 05 March, 2024

तेजयुग न्यूज़

स्थापना दिवस 2024

• वर्ष/year : 01 • अंक/issue : 64 • पृष्ठ/page : 12 • मूल्य/rate : 3 ₹

हापुड़ से प्रकाशित / Published From Hapur



UPHIN/2023/51292

सदन में नोट लेकर दिया वोट या भाषण तो चलेगा केरा

सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को पैलट

को पलट दिया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बोट के बदले नोट मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा। यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट की सर्विधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। इनकारे के फैसले को पैलट दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को पैलट दिया है। 1998 में 5 जजों की सर्विधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पैलटने के चलते अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं।

खल हो जाती है ईंगानदारी : सीजेआई की अध्यक्षता वाली बैंच ने संभाली से दिए गए अहम फैसले में कहा है कि विधायिक के किसी सदस्य द्वारा किया गया ग्राहकाचार या



रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमनादारी को खत्म कर देती है।

सांसदों को छूट से अलगना : सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने विवाद के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है। ब्याच सांसदों पर इससे छूट मिलनी चाहिए। वात से हम असहमत हैं और बहुमत से इसे खारिज करते हैं।

नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसला, जिससे रिश्वत लेने के लिए इस्तेमाल की गयी थी। वह

7 सदस्यीय पीठ ने सुनाया फैसला

बात दें कि 5 सदस्यीय पीठ ने इस केस से जुड़े मामले को व्यापक और जनरित से जुड़ा हुआ मानते हुए 7 सदस्यीय पीठ को सोपं दिया था। तब कहा गया था कि यह मामला राजनीतिक सदाचार से जुड़ा हुआ है। यह भी कहा गया था कि संसद और विधायक सभा सदस्यों को छूट का प्रावधान इसलिए दिया गया है, ताकि वे मुक्त वातावरण और बिना किसी परिणाम की चिंता के अपने दायित्व का पालन कर सकें।

किस मुद्दे से जुड़ा है मामला

दरअसल, यह मामला जामुमो के सांसदों के शिविर कांड पर आए आदेश से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विवाद कर रहा था। आरोप था कि सांसदों ने 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के लिए वोट दिया था। इस मामले पर 1998 में 5 जजों की बैंच ने फैसला सुनाया था। लेकिन अब 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पैलट दिया है। यह मुद्दा दोबारा तब उठा, जब जमुमो की विधायक सीता सोरेन ने अपने दिवालाक जारी किया। आपाराधिक कार्रवाई को रद्द करने की वाचिक दायित्व की ऊंचाई से जुड़ा हुआ है। इन्होंने 2012 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकता है।

सांसदों को छूट से अलगना : सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने विवाद के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है। ब्याच सांसदों पर इससे छूट मिलनी चाहिए। वात से हम असहमत हैं और बहुमत से इसे खारिज करते हैं।

नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसला, जिससे रिश्वत लेने के लिए कहा गया था कि विधायिक के किसी सदस्य द्वारा किया गया था। वह

यह पीएम मोदी को बचाने की आखिरी कोशिश : राहुल

तेजयुग न्यूज़



नई दिल्ली : चुनावी बॉन्ड को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर भाजपा पर दबावावर हो गए। दरअसल, भारतीय स्टेट बैंच ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के लिए समय बढ़ावा दिया है। ब्याच सांसदों पर इससे छूट मिलती है। उन्होंने एकस पर कहा कि आप क्रोनेलोंजी समझिए कि

निर्देश दिए थे कि छह मार्च तक चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

यह न्याय का मजाक : कांग्रेस समाजसिविक जयवरम में इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने एकस पर कहा कि आप क्रोनेलोंजी के लिए समय दिया जाए। बता दें, पिछले माह कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

पहले चुनाव और फिर चुनावी बॉन्ड का खुलासा करने में बाल रहा है। इसमें बोन्डीजी को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर्णी का विपरीत है। इसमें समय बढ़ावा दिया जाए। बता दें, पिछले माह की आखिरी कोशिश के लिए चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर्णी का विपरीत है। इसमें समय बढ़ावा दिया जाए। बता दें, पिछले माह की आखिरी कोशिश के लिए चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर्णी का विपरीत है। इसमें समय बढ़ावा दिया जाए। बता दें, पिछले माह की आखिरी कोशिश के लिए चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर्णी का विपरीत है। इसमें समय बढ़ावा दिया जाए। बता दें, पिछले माह की आखिरी कोशिश के लिए चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर्णी का विपरीत है। इसमें समय बढ़ावा दिया जाए। बता दें, पिछले माह की आखिरी कोशिश के लिए चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर्णी का विपरीत है। इसमें समय बढ़ावा दिया जाए। बता दें, पिछले माह की आखिरी कोशिश के लिए चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर्णी का विपरीत है। इसमें समय बढ़ावा दिया जाए। बता दें, पिछले माह की आखिरी कोशिश के लिए चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर्णी का विपरीत है। इसमें समय बढ़ावा दिया जाए। बता दें, पिछले माह की आखिरी कोशिश के लिए चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर्णी का विपरीत है। इसमें समय बढ़ावा दिया जाए। बता दें, पिछले माह की आखिरी कोशिश के लिए चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर्णी का विपरीत है। इसमें समय बढ़ावा दिया जाए। बता दें, पिछले माह की आखिरी कोशिश के लिए चुनावी बॉन्ड को बचाने की अखिरी कोशिश करार दिया जाए।

एसबीआई का कदम आशंकाएं पैदा कर रहा है। यह न्याय का मजाक है। उन्होंने एकस पर कहा कि यह डिजिटल टॉल के अलावा, जीर